बना दिया जाए या उत्तरांचल कर दिया जाए, यह अलग व्यवस्था है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था जो केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार ने स्वयं इस संबंध में कुछ सूचनाएं प्रदेश सरकार से मांगी थी और मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 1991 का जवाब 4 मार्च, 1992 को जितनी भी सूचनाएं थी भारत सरकार को उपलब्धबने करा दी हैं। लेकिन यह क्षेत्र अलग यह एक अलग प्रश्न है। इस क्षेत्र क विकास होना चाहिए और इस प्रदेश के इस क्षेत्र में जो गरीबी है, जो लोगों का असंतोष है उसको दूर करने के लिए भरत सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह इस संबंध में शीघ्र ही कदम उठायेगी जिससे कम से कम इस क्षेत्र लोग अपने को उपेक्षित महसूस न करें।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मैं आदरणीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए एक बात जोड़ना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो तराई का क्षेत्र है आजतक वहां भूमि सुधार नहीं हुआ और एक ओर गरीब और भूमिहीन खेतिहर मजदूर झोपड़ियों में रह रहे है और दूसरी तरफ हजारों-हजार एकड़ के फार्म एक-एक व्यक्ति के पास हैं। एक तो भूमि सुधार होना चाहिए और दूसरे टिहरी बांध जो खटाई में पड़ा हुआ है और जो प्रोसपैरिटी इस क्षेत्र में ला सकता है वह टिहरी डैम राजनीतिक कारणों की वजह से पड़ा हुआ है उसका निर्माण होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके।

Likely closure of Barauni oil refinery due to financial constraints

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा जो आज विशेष लोक महत्व का विषय है वह बिहार के बरौनी ऑयल रिफाइनरी की जो वतमान स्थिति है उसस सम्बन्धित है। बिहार में पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत इस समय जो मुख्य रूप से उपक्रम कार्यरत हैं उनमें से सिदरी, बरोनी, बोकारो, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची और कोल इंडिया के जो उपक्रम है मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसमें सिदरी फर्टीलाइजर कारपोरेशन और बरोनी ऑयल रिफाइनरी ऐसे उपक्रम है जिनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। विगत कई वर्षों से ये घाट में चल रहे हैं और घाट में चलने के कारण सरकार को जहां एक ओर इन पर अधिक ध्यान देना चाहिए वहां सरकार अधिक तो क्या पूरा भी ध्यान नहीं दे रही है जिसके कारण ये दोनों उपक्रम बराबर बंद होने के क्रम में रहते हैं। मुख्य रूप से इसका कारण यह है कि सिदरी को यहां माडर्नाइजशन के लिए फंड मिलना चाहिए वहां दुसरेदूसरे फर्टीलाइजर कारपोरेशन को तो मिले लेकिन सिदरी में भारत सरकार ने कोई पैसा इन्वस्ट नहीं कियरी और दूसरे ओर बरोनी ऑयल रिफाइनल जिसके बारे में मुख्य रूप से मैं सवान उठा रहा हूं जिसकी क्षमता 4 मिलियले टन क्रूड ऑयल शोधन की है। 4 मिलियान टन क्रूड ऑयल शोधन की क्षमता वय रिफाइनरी को इस समय केवल 2 मिलिन टन क्रूड ऑयल मिलता है, मतलब आधा। वह भी कभी-कभी नहीं मिलता यानी उससे कम मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है जिस समय यह उपक्रम बना था देश में इस तरह के उपक्रम बहुत कम थे। देश में उस समय जब इसका निर्माण हुआ था तो लोगों को आशा बंधी थी दो कारणों से। एक तो पूर्वांचल असम से क्रूड ऑयल वहां आना था जिसकी वजह से उसकी सप्लाई हर जगह होती थी। उस समय देश में बहुत जगहों में हमारे परिशोधन कारखाने नहीं थे। दूसरी बात यह है कि बिहार का जो बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर बिहार में रहता है उसकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए और उसका विकास करने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए बरोनी ऑयल रिफाइनरी का निर्माण हुआ था। हमारे मित्र श्री अहलुवालिया जी वहीं के रहने वाले हैं, वहीं रहते हैं। वह अच्छी तरह से इन समस्याओं को जानते हैं।

2·00 P.M.

लेकिन मैं आपसे इस संबंध मे जो अपील करना चाहता हूं वह यह है कि अभी आसाम में प्रधान मंत्री जी ने जाकर, पहले से तो वहां था ही, लेकिन फिर अभी जाकर प्रधान मंत्री ने एक नई रिफायनरी की स्थापना के लिए शिलान्यास किया है। उसके होने के बाद संभव है कि यह भी मिले और यह बंद कर दिया जाए : वहां इसको लेकर बराबर लोगों के अन्दर चिन्ता व्याप्त है और चूंकि हजारों लोग रोजगारी के शिकार हो जाएंगे, इसलिए उनमें चिन्ता व्याप्त है। मैं सरकार से एक बात इस संबंध में बड़े ही विनय के साथ कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की पालिसी क्या है, मुझे यह बात समझ मे नहीं आती है और बहुत चिन्ता व्याप्त है। सरकारी उपक्रम जितने भी है, चाहे सरकार के है, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, लाभ भी अच्छा होता है, जिनकी संभावना भी अच्छी है, उनको एसिस्टेंस न दे करके सरकार चाहती है कि उनको बंद करके प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाय। पब्लिक सेक्टर को किसी तरह से बदनाम करके प्राइवेट सेक्टर मे दे दिया जाय। मै एक उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार की प्राईसिंग आफ पट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक किताब भारत सरकार की ओर से निकली है, उसके केवल एक पैरा को, लास्ट पैरा को, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

> "The Government is also speeding up the expansion of existing refineries and the setting up of new refineries in the private, joint and public sectors. The capacity of existing refineries is planned to be increased by 7.5 million tonnes. Also, new refineries are being set up at Mangalore, Karnal and Numaligarh. In addition, three more grassroot refineries in the Eastern, Central and Western parts of the country are to be implemented with maximum speed. The new policy facilities establishment of refineries in the joint sector who will raise their own foreign exchange and rupee resource."

उपसभाध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं भारत सरकार से यह अपील भी करना चाहता हूं कि उसके पास जब बरौनी आयल रिफाइनरी जैसी तेल शोधक कारखाना है जिसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि चार मिलियन टन क्रूड आयल का शोधन वहां पर किया जा सकता है और बहुत ही मार्डन ढंग से यह तैयार किया गया है, उसके प्रति इस तरह की उपेक्षा नीति रखकर नई आयल रिफाइनरी खोलने के लिए और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए और जिनके लिए फौरन एसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए सरकार क्यों प्रयास कर रही है? इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में एक बयान दे और दे और तत्काल बरौनी आयल रिफाइनरी की जो क्षमता है चार मिलियन टन क्रूड आयल की, जिसमें उसको दो मिलियन टन क्रूड आयल ही मिल रहा है, वह पूरा उसको चार मिलियन टन क्रूड आयल मिले जिससे उसकी क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन हो और लोगों को काम भी मिले।

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शंकर दयाल सिंह जी द्वारा उठाये गये विशेष उल्लेख का पूरा समर्थन करते हुए आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बरौनी आयल रिफाइनरी जो आसाम क्रूड पर बेस करके बनाई गई थी और इसे जो भी क्रूड मिल रहा था, जब आसाम का आन्दोलन चल रहा था तो कम मिल रहा था, लेकिन आज इसकी बड़ी क्षीण अवस्था इस कम्पनी की हो गई है। सारी तकनीक उपलब्ध है, मशीनरी उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है, लेकिन क्रूड आयल नहीं मिलता है जिसको यह प्रोसेस कर सके। इस संदर्भ में एक प्रपोजल बनाया गया था कि हल्दिया से जो पाइप लाइन आती है, जिसमें कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी पम्प किये जाते है, इस तरफ लाई जाय जो यू०पी० की तरफ जाती है और बरौनी होकर आती यह मेरी मांग है। हल्दिया से क्रूड पाइप लाइन दी जाय, क्रूड आयल सप्लाई है

पाइप लाइन ली जाय। हल्दिया में जो रिफाइनरी चल रही है वह पूरी की पूरी फारेन क्रूड आयल पर डिपेन्ड करती है। इसलिए अगर इम्पोर्टेड क्रूड आयल पम्प करके बरौनी भेजा जाय तो मैं समझता हूं कि जो चार मिलियन टन की उसकी केपीसिटी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अन्यथा जो अवस्था है, वहां बरौनी थर्मल पावर स्टेशन वही फरनिश आयल लेकर चलता है, जैसा कि आपको ज्ञात है। बिहार में बिजली की अवस्था बहुत खराब है और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को अगर फर्निस्ड आयल न मिला तो वह भी बंद हो जायेगा। इसके साथ ही वहां जो हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की फर्टिलाइजर यूनिट है वह इस आयल रिफाइनरी से नेफ्था लेती है, जो उसका रा-मेटीरियल है। उसे भी अगर नेफ्था नहीं मिलेगा तो वह कारखाना बंद हो जायेगा। इस कारखाने के कमजोर हो जाने से, रुग्ण हो जाने से और भी जितनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वहां है वे रुग्ण हो चुकी है। अगर आप इस इलाके का दौरा करें तो पायेंगे कि उस इलाके में सैकड़ों स्माल स्केल इंडस्ट्रीज है जो बरौनी आयल रिफाइनरी, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को कैटर करने के लिये चलती हैं. इन सब की अवस्था खराब है। मुझे ज्ञात है कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका एश्योरेंस दिया था और उस इलाके में एक पेट्रो कैमिकल काम्पलेक्स लगाने का अनुमोदन किया था। पर आज तक वह अनुमोदन पत्र हमारे पेट्रोलियम विभाग मे पड़ा हुआ है, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही हुई है। वहां के लोग, जिस इलाके का सर्वेक्षण करके बताया गया था कि यह जमीन एक्वायर होगी, उस जमीन के बारे मे, उस जमीन के मालिक आज तक इंतजार कर रहे है कि कब यह जमीन एक्वायर होगी और कब यह पेट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स बनेगा। मेरी मांग है कि सिर्फ बरौनी आयल रिफाइनरी के लिये फारेन क्रूड लेने की ही आप व्यवस्था नहीं करेंगे बल्कि वहां पर पेट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स, जिसके लिये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने वचन दिया था, उसको निभायेंगे। यही कहते हुए मैं इस बात का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Shri Kamal Morarka. Not present.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Sir, may I seek some clarification? According to this Revised List of Business, the Private Members' Business would start at 2 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): No. It is at 2.30 p.m.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): 2 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): It is at 2.30 p.m. I think it is a printing mistake. It has been our convention that we take up the Private Members' Business at 2.30 p.m. Today also, we will take it up at that

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Can you finish all the special mentions before that?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): I am trying to finish them. Shrimati Jayanthi Natarajan. Not present.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Mr Vice-Chairman, in Hindi it is printed as "2.30".

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): As I told you, it is a printing mistake. The Secretariat also has informed me that it is a printing mistake. I am sorry for the inconvenience caused to hon. Members. Shri Mentay Padmanabham.

Impending changes in Textbooks used in total literacy programme by Andhra Pradesh Government